



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2012/आषाढ़ 14, 1934

No. 158]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2012/ASADHA 14, 1934

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 28 जून, 2012

सं. टीएएमपी/21/2011-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, क्यू 7 क्षेत्र में एक्जिम कंटेनरों को प्रक्रिया-पूर्व सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारों के अनुमोदन की मांग के बारे में कोचीन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/21/2011-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(जून, 2012 के 18वें दिन पारित)

यह मामला क्यू-7 में एक्जिम कंटेनरों को प्रक्रिया-पूर्व सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारों के अनुमोदन मांग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 4 अप्रैल, 2011 से संबंधित है।

2.1. सीओपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i). इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड आरजीसीटी परिसर से बाहर प्री-स्टेज जांच क्षेत्र में परिचालन कर रहा था। कंटेनर प्रहस्तन परिचालनों को 11/02/2011 से आरजीसीटी से आईसीटीटी में स्थानांतरित किया गया है और सीओपीटी ने आईसीटीटी को/से एक्जिम कंटेनरों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस सुविधा को जारी रखने के लिए तत्काल आवश्यकता की वजह से 21/02/2011 से क्यू-7 क्षेत्र पत्तन के भीतर पूर्व-स्टेज परिचालन शुरू किए हैं।
- (ii). तथापि, क्यू-7 क्षेत्र में उक्त परिचालनों के लिए कोई टीएमपी अनुमोदित दरें नहीं हैं।
- (iii). (क). निम्नलिखित दूरे तदर्थ आधार पर प्रस्तावित की गई हैं और इसके लिए सहमति पत्तन उपयोक्ताओं से प्राप्त की गई है:-

- (i). निकासी के लिए आयात तथा निर्यात कंटेनर की जांच के लिए प्रभार:

20'	40'	45'
₹ 400		

- (ii). कंटेनरों के लिए लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ प्रभार:

प्रकार	विदेशी (₹ में)			तटीय (₹ में)		
	20'	40'	45'	20'	40'	45'
लदा हुआ	570.24	855.36	1140.48	342.14	513.22	684.29
खाली	178.20	267.30	356.40	106.92	160.38	213.84

- (iii). कंटेनरों के लिए प्रशीतन प्रभार - बिजली आपूर्ति तथा अनुवीक्षण प्रभार प्रति 4 घंटे अथवा उसका भाग।

विदेशी (अमेरिकी डॉलर)			तटीय (₹)		
20'	40'	45'	20'	40'	45'
3.18	4.76	6.35	138.40	207.58	276.80

- (iv). कंटेनरों पर भूमि किराया:

यहां पर निर्धारित निःशुल्क अवधि अंगीकृत किए बिना पत्तन दरमान के 5.1.2 में निर्धारित दरों पर उतारे जाने की तारीख के अगले दिन से भंडारण सुविधा प्राप्त करने वाले कंटेनरों के लिए भूमि किराया वसूल किया जाएगा। (सीओपीटी ने अपने दरमान के प्रासंगिक पृष्ठ भेजे हैं।)

(ख). सीओपीटी ने करस्टम क्लियरिंग हाऊस एजेंट्स असोसिएशन (सीसीएचए) के साथ 28 फरवरी 2011 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भेजी है। उक्त बैठक में लिए गए निर्णय नीचे सारबद्ध किए गए हैं:-

- (i). आईजीटीपीएल द्वारा प्रभारित दरें कंटेनर के आकार और प्रक्रिया के समय पर निर्भर करते हुए रु0 350/- से रु0 600/- तक भिन्न-भिन्न होता है। सीमाशुल्क जांच की सेवा को और अधिक उपयोक्ता उन्मुख बनाने के लिए, आकार तथा समय पर ध्यान दिए बिना दर को रु0 400/- प्रति कंटेनर करने का बैठक में निर्णय लिया गया था।
- (ii). सीओपीटी रीच स्टेकर सेवा की व्यवस्था करते हुए लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ सुविधा भी प्रदान करेगा। आरजीसीटी पर आईजीटीपीएल द्वारा प्रभारित दर उक्त सेवा के लिए सीओपीटी द्वारा जारी रहेगी।
- (iii). ट्रेड ने आईसीटीटी में उपलब्ध सुविधा के अलावा आरजीसीटी यार्ड में प्रशीतन भंडारण सुविधा की आवश्यकता को प्रमुखता से पेश किया था। सीओपीटी अपने क्यू-7 यार्ड में प्रशीतन भंडारण परिचालन शुरू करने के लिए सहमत था। आईजीटीपीएल द्वारा पहले से प्रभारित दरें सेवा प्रदान करने के लिए सीओपीटी द्वारा जारी रखी जाएगी।
- (iv). भंडारण सुविधा प्राप्त करने के लिए जमीन पर उतारे गए कंटेनरों से यहां पर निर्धारित निःशुल्क अवधि अंगीकृत किए बिना सीओपीटी के दरमान के खंड 5.1.2 में निर्धारित दरों पर उतारे जाने की तारीख से अगले दिन से भूमि किराया वसूल किया जाएगा।

सीसीएचए बैठक में लिए गए उपर्युक्त निर्णयों पर सहमत था। सीसीएचए आईसीटीटी के माध्यम से कंटेनर प्रहरस्तन के लिए सकल प्रणाली लागत नियंत्रित करने के लिए कम लागत वाली प्री-प्रक्रिया सुविधा की जरूरत पर भी ध्यान आकर्षित किया है।

- (iv). उपर्युक्त (ख) और (ग) पर प्रस्तावित लिफ्ट ऑन तथा लिफ्ट ऑफ के लिए तदर्थ दरें और प्रशीतन प्रभार पिछले कई वर्षों से आरजीसीटी में समान सेवाओं के लिए आईजीसीटीपीएल द्वारा प्रभारित दरों के बराबर हैं, जबकि उपर्युक्त (क) पर दी गई दर आरजीसीटी के बाहर आईजीसीटीपीएल द्वारा प्रभारित प्रभारों की औसत है।
- (v). सीओपीटी ने प्रस्तावित दरों को 21 फरवरी 2011, इस प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन तदर्थ आधार पर प्री-प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख, से लागू किए जाने के बारे में ट्रेड को सूचित करने के लिए एक परिपत्र दिनांक 4 अप्रैल 2011 जारी किया था।

2.2. सीओपीटी ने इस प्राधिकरण से तदर्थ आधार पर दरें अनुमोदित करने का अनुरोध किया था और 1 अप्रैल 2012 से देय प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव के साथ 'लागत जमा' आधार पर क्यू-7 क्षेत्र में प्री-स्टेज गतिविधि के लिए विस्तृत प्रस्ताव जमा करने के लिए सहमत था। (तत्पश्चात, सीओपीटी ने सितम्बर 2011 में अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया था। इसने सामान्य संशोधन प्रस्ताव के साथ भेजे गए प्रस्तावित दरमान में प्री-प्रक्रिया सुविधा के लिए प्रस्तावित प्रभार शामिल किए हैं, जैसाकि ऊपर बताया गया है)।

3. उपर्युक्त क्र. सं. iii (क) (i) में उल्लिखित कंटेनरों की जांच के लिए सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ दर सीओपीटी द्वारा यथा उल्लिखित आरजीसीटी के बाहर आईजीटीपीएल द्वारा प्रभारित दरों की औसत है। उपर्युक्त क्र.सं. iii क (ii) & (iii) में क्रमशः उल्लिखित लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ सेवाओं तथा प्रशीतन अनुवीक्षण सेवाओं के लिए सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ दरें इस प्राधिकरण द्वारा आरजीसीटी परिचालनों के लिए आईजीटीपीएल हेतु अनुमोदित दरों के अनुसार हैं।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीओपीटी का प्रस्ताव उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त हुई टिप्पणियां सीओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजी गई थीं। सीओपीटी ने भी उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी अभ्युक्तियां भेजी थीं।

5. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 28 मार्च 2012 को कोवीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) परिसर में आयोजित की गई थी। सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव का मास्टर प्लान प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, सीओपीटी तथा संबंध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता अभिलेखों ने अपने-अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे।

6. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है—

(i). आईजीटीपीएल द्वारा कंटेनर परिचालनों को 11 फरवरी 2011 से आरजीसीटी से आईसीटीटी में स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप, सीओपीटी आईसीटीटी, वालारपादम में सुविधाओं के अभाव में, पत्तन के भीतर ब्यू-7 क्षेत्र में, एक्जिम कंटेनरों को आईसीटीटी से/को ग्री-स्टेज सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। सीओपीटी ने ग्री-स्टेज सेवाओं, अर्थात् (i) आयात/निर्यात कंटेनरों की जांच, (ii) कंटेनरों का लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ, (iii) बिजली आपूर्ति तथा प्रशीतन अनुवीक्षण प्रभार और (iv) भूमि किराया के लिए प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया है। सीओपीटी का मौजूदा दरमान सिवाय भूमि किराये की वसूली के इन सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है। 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 में कहा गया है कि जब कभी अधिसूचित दरमान में सेवा/कार्यों के लिए विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं हो तो पत्तन परिचालक उपयुक्त प्रस्ताव जमा कर सकता है।

(ii). सीओपीटी ने यह कहते हुए तदर्थ आधार पर प्रभारों का प्रस्ताव किया है, कि लागत आधारित प्रस्ताव दरमान के सामान्य संशोधन, जो 1 अप्रैल 2012 से देय है, के इसके प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सीओपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के साथ इसके द्वारा प्रेषित प्रस्तावित दरमान में इन सेवाओं की दरें शामिल की हैं। सीओपीटी का उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव इस प्राधिकरण की कार्यवाहियों के अधीन है। चूंकि सामान्य संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने और संशोधित दरमान को अधिसूचित किए जाने में कुछ और समय लगेगा, सीओपीटी द्वारा मांगे गए अपेक्षित ब्योरो/स्पष्टीकरणों के जमा करने के लिए समय के विस्तार के मद्देनजर, इसलिए तदर्थ दरों के अनुमोदन के प्रस्ताव को विचार के लिए लिया गया है।

(iii). दो प्रशुल्क मदों, अर्थात् लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ सेवाएं तथा बिजली आपूर्ति एवं प्रशीतन अनुवीक्षण सेवाओं के लिए सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें आरजीसीटी में इसके परिचालनों के लिए आईजीटीपीएल हेतु इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क के बराबर हैं। भूमि किराया सीओपीटी के दरमान में निर्धारित प्रशुल्क के मौजूदा स्तर पर प्रस्तावित किया गया है। कंटेनरों की जांच के लिए सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित ₹ 400/- की दर आईसीटीटी में कंटेनर प्रहस्तन परिचालनों की शुरुआत से पहले, आरजीसीटी के बाहर आईजीटीपीएल द्वारा प्रभारित प्रभारों की औसत बताई गई है। आईजीटीपीएल के आरजीसीटी से आईसीटीटी में विस्थापन के परिणामस्वरूप, सीओपीटी ने आईसीटीटी को और से कंटेनरों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने के लिए ग्री-प्रक्रिया के प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया है।

(iv). (क). जैसाकि पहले बताया गया है, सीओपीटी ने आदेश सं. टीएएमपी/34/2005-आईजीटीपीएल दिनांक 6 अक्टूबर 2005 द्वारा आईजीटीपीएल के दरमान में यथा निर्धारित लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ सेवा तथा प्रशीतन अनुवीक्षण सेवा के लिए दरें अंगीकृत करने का प्रस्ताव किया है। संयोगवश, प्रस्तावित दरें आदेश सं. टीएएमपी/34/2005-आईजीटीपीएल दिनांक 6 अक्टूबर 2005 में निर्धारित खंड 2 (vii) के साथ पठित खंड 3.2.2 और 3.5 द्वारा आईजीटीपीएल के दरमान में अनुमोदित दरों के अनुसार पाई गई हैं।

(ख). मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.12 के अनुसार, जब एक नई सुविधा शुरू की जाती है, स्वीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक प्रशुल्क तुलनीय सुविधाओं के लिए समान पत्तन पर मौजूदा प्रशुल्क स्तर से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसी तुलना उपलब्ध नहीं हो तो तुलनीय निकटवर्ती पत्तन पर प्रचलित प्रशुल्क संदर्भ स्तर रूप में सुविचारित किया जाएगा। ऐसे अंगीकृत प्रारंभिक प्रशुल्क परिचालनों के प्रथम वर्ष के लिए वैध होगा उसके बाद संशोधित प्रशुल्क स्वीकार्य लागत तथा परिचालक के निवेश के आधार पर निर्धारित

किया जाएगा। जैसाकि पहले बताया गया है, आदेश दिनांक 23 फरवरी 2010 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीओपीटी का मौजूदा दरमान लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ तथा प्रशीतन अनुवीक्षण सेवाओं के लिए प्रभार निर्धारित नहीं करता है। यह प्रतीत होता है कि ऐसी सेवाओं के लिए इसके अपने दरमान में प्रभारों के अभाव में, सीओपीटी ने समान सेवाओं के लिए आईजीटीपीएल के दरमान में निर्धारित प्रभारों को अंगीकृत किया है। अतः सीओपीटी द्वारा आईजीटीपीएल के दरमान में निर्धारित प्रभारों का अंगीकरण प्रशुल्क दिशानिर्देश स्थिति का अनुसरण करता है।

(ग). जहां तक प्री-प्रक्रिया सुविधा पर कंटेनर द्वारा स्थान अधिग्रहण करने के लिए प्रभारों की वसूली का संबंध है, सीओपीटी ने बिना निःशुल्क अवधि स्वीकृत किए इसके अपने दरमान में निर्धारित भूमि किराया लागू करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रतीत होता है कि सीओपीटी ने प्री-प्रक्रिया सुविधा पर कंटेनरों के लिए निःशुल्क अवधि स्वीकृत नहीं करने का प्रस्ताव किया है क्योंकि कंटेनर इसके बर्थों पर प्रहस्तन के लिए नहीं हैं और यह ऐसे कंटेनरों पर घाटशुल्क तथा प्रहस्तन प्रभार वसूल नहीं कर रहा है।

(घ). जैसाकि पहले बताया गया है, सीओपीटी ने कंटेनरों के आकार तथा प्रक्रिया के समय पर ध्यान दिए बिना ₹0 400/- प्रति कंटेनर की दर से कंटेनरों की जांच के लिए प्रभारों की वसूली करने का प्रस्ताव किया था।

इस प्राधिकरण द्वारा गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए दाखिल किए गए प्रस्ताव का निपटान करते हुए पारित किए गए आदेश सं. टीएमपी/48/2011-जीटीआईपीएल दिनांक 19 जनवरी 2012 में, सीमाशुल्क जांच के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए कंटेनरों की स्टेकिंग के लिए निर्धारित दरें कंटेनर के आकार पर निर्भर करते हुए ₹0 118.35 से ₹0 236.70 के बीच हैं। तथापि, सीओपीटी का प्रस्ताव कंटेनरों के आकार पर ध्यान दिए बिना एकल दर के निर्धारण के लिए है।

हालांकि कंटेनरों के ऑन-व्हील निरीक्षण से संबंधित ऐसी दरें कंटेनरों की जांच के लिए सीआईटीपीएल, सीसीटीपीएल और एनएसआईसीटी द्वारा परिचालित कंटेनर टर्मिनलों के दरमान में दरें निर्धारित की गई हैं जो सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दर से तुलना के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते। कंटेनर के आकार पर ध्यान दिए बिना ₹0 170/- प्रति कंटेनर की दर सीमाशुल्क जांच अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए कंटेनरों की स्टेकिंग के लिए आदेश सं. टीएमपी/53/2007-जेएनपीटी दिनांक 18 फरवरी 2011 द्वारा अनुमोदित जेएनपीटी के मौजूदा दरमान में निर्धारित की गई है। तथापि, वीसीटीपीएल तथा एबीजीकेसीटीएल द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्तावों का निपटान करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/10/2011-वीसीटीपीएल दिनांक 11 अक्टूबर 2011 और टीएमपी/40/2010-एबीजीकेसीटीएल द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पारित किए गए प्रशुल्क आदेश में, क्रमशः ₹0 400/- और ₹0 356/- की दर टर्मिनल के भीतर सीमाशुल्क जांच के लिए कंटेनरों के आकार पर ध्यान दिए बिना निर्धारित की गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दर वीसीटीपीएल के लिए निर्धारित दर के बराबर हैं और एबीजीकेसीटीएल के लिए निर्धारित दर के करीब हैं।

(ङ). इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित कंटेनरों की जांच के लिए दर वीसीटीपीएल तथा एबीजीकेसीटीएल के दरमान में निर्धारित दर से तुलनीय है, सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ सेवा तथा बिजली आपूर्ति एवं प्रशीतन अनुवीक्षण सेवा के लिए दरें प्रशुल्क दिशानिर्देश स्थिति का अनुसरण करता है और सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित भूमि किराया पत्तन के दरमान में पहले से निर्धारित दरों से लिया गया है और यह स्थिति स्वीकार करते हुए कि उपयोक्ताओं ने प्रस्तावित दरों का समर्थन किया है, यह प्राधिकरण पत्तन के क्यू-7 क्षेत्र में प्री-प्रक्रिया सेवाएं प्रदान करने के लिए बिना किसी बदलाव के सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

24/65 GZ/12-2

- (v). शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने अनुरोध किया है कि यह करने के लिए टीएमपी द्वारा उल्लिखित सामान्य शर्त कि भूमि किराया परित्यक्त एफसीएल/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों के मामले में 75 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, को यह सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रशुल्क खंड में ही शामिल किया गया है कि पत्तन सामान्य नियम का पालन करता है। सीओपीटी के मौजूदा अनुमोदित दरमान में प्रस्तित्व एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों पर भंडारण प्रभारों को लागू करने को शासित करने वाली शर्तें पहले से दी गई हैं, जोकि सीओपीटी पर बाध्यकारी है। अतः सीओपीटी के दरमान में उक्त शर्तों का निर्धारण मात्र दोहराव होगा।
- (vi). मरीन उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए) ने शिपिंग कंपनियों द्वारा प्रभारित प्रभारों के बारे में चिंता व्यक्त की है। शिपिंग कंपनियों द्वारा प्रभारित प्रभार इस प्राधिकरण के विनियामक कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।
- (vii). कॉफी बोर्ड द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में कि क्यू-7 क्षेत्र में प्रोद्भूत लागत तब तक सीओपीटी द्वारा वहन की जानी चाहिए जब तक आईसीटीटी में सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं, यह स्वीकार करना होगा कि पत्तन क्यू-7 क्षेत्र में अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसमें पत्तन को अतिरिक्त लागत शामिल है। इसलिए, पत्तन से यह उम्मीद करना सही नहीं है कि ऐसी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं।
- (viii). 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 और 2.17.2 के अनुसार, जब कभी किसी सेवा/कार्गो के लिए विशिष्ट प्रशुल्क अधिसूचित दरमान में उपलब्ध नहीं हो, पत्तन उपयुक्त प्रस्ताव जमा कर सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ, प्रस्तावित दर तब तक तदर्थ आधार पर वसूल की जा सकती है जब तक दर को अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है। तथापि, तदर्थ दर तुलनीय सेवाओं के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर अवश्य विपथित की जानी चाहिए और इस पर पत्तन तथा संबद्ध उपयोक्ता परस्पर रूप से सहमत होने चाहिए। यह पत्तन तदर्थ आधार प्रस्तावित प्रभार 21 फरवरी 2011 से पहले से वसूल कर रहा है जैसाकि उपयोक्ताओं की सहमति से पत्तन द्वारा जारी किए गए ट्रेड परिपत्र से देखा जा सकता है। सीओपीटी ने उपयोक्ताओं की सहमति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भेजा था और प्रस्तावित प्रभार तुलनीय सेवाओं के लिए अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर विपथित किए गए हैं सिवाय कंटेनरों की जांच के प्रभारों के जोकि बीसीटीपीएल तथा एबीजीकेसीटीएल के दरमान में निर्धारित दरों से भी तुलनीय है, जैसा पहले बताया गया है। 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.17.4 इस प्राधिकरण को अधिकार देता है कि तब तक पूर्वव्यापी प्रभाव से तदर्थ तरीके से अंगीकृत अंतरिम दर स्वीकार करे जब तक पूर्वव्यापी प्रभाव से कुछ संशोधन की अपेक्षा नहीं पाई जाती है। चूंकि सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है, इसलिए यह प्राधिकरण 21 फरवरी 2011, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक प्रस्तावित दरों के कार्यान्वयन की तारीख, से तदर्थ तरीके से पत्तन द्वारा प्रभारित दरें स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त है।
- (ix). चूंकि यह पत्तन प्रस्तावित प्रभारों की वसूली पहले से शुरू कर चुका है, इसलिए अनुमोदित दरें बिना किराी लीड समय के इस मामले में पारित आदेश की अधिसूचना पर प्रभावी होगी।
- (x). प्रशुल्क दिशानिर्देश 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र विनिर्दिष्ट करता है। तथापि, विषय प्रस्ताव में सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें तदर्थ आधार पर हैं। इसके अलावा, सीओपीटी ने अपने दरमान, जो इस प्राधिकरण की कार्यवाहियों के अधीन है, के सामान्य संशोधन के लिए इसके प्रस्ताव में इन सेवाओं के लिए प्रभारों को शामिल किया है। ऐसी स्थिति में, इस मामले में अनुमोदित दरों की वैधता तब तक निर्धारित करना उपयुक्त होगा जब तक पत्तन के दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख सामान्य संशोधन प्रस्ताव में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है।
- (xi). प्री-स्टेज सेवाओं के लिए प्रभारों को अध्याय V – कंटेनर संबंधित प्रभार के अधीन पृथक अनुसूची के रूप में सीओपीटी के दरमान में शामिल किया गया है।

8. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित प्रभार अनुमोदित करता है जिन्हें सीओपीटी के मौजूदा दरमान के अध्याय V के अधीन अनुसूची 5.4 रूप में शामिल किया गया है:

"5.4. आईसीटीटी को/से कंटेनरों के लिए प्री-स्टेज सेवाओं हेतु प्रभार

(क). निकासी के लिए आयात तथा निर्यात कंटेनर की जांच के लिए प्रभार:

20'	40'	45'
रु० 400		

(ख). कंटेनरों के लिए लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ प्रभार:

प्रकार	विदेशी (रु० में)			तटीय (रु० में)		
	20'	40'	45'	20'	40'	45'
लदा हुआ	570.24	855.36	1140.48	342.14	513.22	684.29
खाली	178.20	267.30	356.40	106.92	160.38	213.84

(ग). कंटेनरों के लिए प्रशीतन प्रभार – बिजली आपूर्ति तथा अनुवीक्षण प्रभार प्रति 4 घंटे अथवा उसका भाग।

विदेशी (रु० में)			तटीय (रु० में)		
20'	40'	45'	20'	40'	45'
3.18	4.76	6.35	138.40	207.58	276.80

(घ). कंटेनरों पर भूमि किराया:

भूमि किराया भंडारण की सुविधा प्राप्त करने वाले कंटेनरों के लिए कंटेनरों को उतारे जाने की तारीख के अगले दिन से, यहां पर निर्धारित निःशुल्क अवधि स्वीकृत किए बिना पत्तन के दरमान की अनुसूची 5.1.2 में निर्धारित दरों पर, वसूल किया जाएगा।"

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/12/असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 28th June, 2012

**No. TAMP/21/2011-COPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Cochin Port Trust seeking approval of charges for providing pre-processing facility to EXIM Containers at Q7 area as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/21/2011-COPT

Cochin Port Trust

Applicant

### ORDER

(Passed on this 18th day of June, 2012)

This case relates to the proposal dated 4 April 2011 received from the Cochin Port Trust (COPT) seeking approval of charges for providing pre-processing facility to EXIM Containers at Q-7 area.

2.1. The main points made by the COPT in its proposal are summarized below:

- (i). India Gateway Terminal Private Limited was operating a pre-stage examination zone outside the RGCT premises. The container handling operations have been shifted from RGCT to ICTT with effect from 11/02/2011 and COPT has

commenced the pre-stage operations inside the Port at Q7 area with effect from 21/02/2011 due to an urgent necessity for continuing the facility for ensuring smooth movement of EXIM containers to/from ICTT.

- (ii). However there are no TAMP approved rates applicable for the said operations at Q7 area.

- (iii). (a). The following rates have been proposed on ad-hoc basis and the consent for the same has been obtained from the port users.

- (i). Charges for examination of import & Export container for clearance:

20'	40'	45'
₹ 400		

- (ii). Lift on /Lift off charges for containers:

Type	Foreign (in ₹)			Coastal (in ₹)		
	20'	40'	45'	20'	40'	45'
Laden	570.24	855.36	1140.48	342.14	513.22	684.29
Empty	178.20	267.30	356.40	106.92	160.38	213.84

- (iii). Reefer charges for containers –

Electricity supply and monitoring charges \*per 4 hours or part thereof.

Foreign (US \$)			Coastal (₹)		
20'	40'	45'	20'	40'	45'
3.18	4.76	6.35	138.40	207.58	276.80

- (iv). Ground Rent on Containers:

Ground Rent will be levied for containers availing storage from the day following the date of grounding at the rates prescribed at 5.1.2 of the Port Scale of Rates without adopting the free period prescribed therein. (The COPT has furnished relevant pages of its SOR.)

- (b). The COPT has furnished a copy of minutes of the meeting held on 28 February 2011 with the Customs Clearing House Agents' Association (CCHAA). The decisions taken in the said meeting are summarised below:

- (i). The rates charged by the IGTPPL varied from ₹350/- to ₹600/- depending on the size of container and the timing of processing. In order to make the service of customs examination more user friendly, it was decided in the meeting to lower the rate to ₹400/- per container irrespective of the size and timing.

- (ii). COPT will also facilitate the lift on / lift off facility by arranging reach stacker service. The rate charged by the IGTPPL at RGCT will be continued by the COPT for the said service.



- (iii). The Trade highlighted the requirement of reefer storage facility at the RGCT yard in addition to the facility available at ICTT. COPT agreed to resume the reefer storage operations at its Q7 yard. The rates previously charged by the IGTPL will be continued by COPT for rendering the service.
- (iv). The containers grounded for availing storage will be charged ground rent from the day following the date of grounding at the rates prescribed in the at Section 5.1.2 of the Scale of Rates of COPT without adopting the free period prescribed therein.

The CCHAA has agreed to the above decisions taken in the meeting. The CCHAA also highlighted the need for a low cost pre-processing facility to control the gross system cost for container handling through ICTT.

- (iv). The ad-hoc rates for lift on and lift off and reefer charges proposed at (b) & (c) above are at par with the rates charged by IGTPL for the same services at RGCT for the last couple of years, while the rate at (a) is an average of the charges levied by IGTPL outside the RGCT.
- (v). The COPT has issued a circular dated 4 April 2011 to the Trade conveying the implementation of the proposed rates with effect from 21 February 2011, the date of commencement of the pre-processing facilities on ad hoc basis subject to approval of this Authority.

2.2. The COPT has requested this Authority to approve the rates on adhoc basis and agreed to submit a detailed proposal for the pre-stage activity at Q7 area on 'cost plus' basis along with the proposal for general revision of tariff which is due from 1 April 2012. (Subsequently, the COPT has filed the proposal for general revision of its Scale of Rates in September 2011. It has included the proposed charges for pre-processing facility, as brought out above, in the proposed Scale of Rates furnished along with the general revision proposal).

3. The adhoc rate proposed by COPT for examination of containers mentioned at Sl. No.iii (a) (i) above is an average of the charges levied by IGTPL outside the RGCT as stated by COPT. The adhoc rates proposed by COPT for lift on / lift off services and reefer monitoring services mentioned at Sl. No.iii a(ii) & (iii) above respectively are in agreement with the rates approved by the Authority for IGTPL for its RGCT operations.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of COPT was forwarded to the user/ user organisations seeking their comments. The comments received from users/ user organisations were forwarded to COPT as feedback information. The COPT has also furnished its remarks on the comments of the users/ user organizations.

5. A joint hearing in this case was held on 28 March 2012 at the Cochin Port Trust (COPT) premises. The COPT made a power point presentation of its proposal. At the joint hearing, COPT and the concerned users/user associations have made their submissions.

2465 GI/12-3

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

7. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). Consequent to the shifting of container operations by IGTPL from RGCT to ICTT from 11 February 2011, the COPT is providing pre-stage services to the EXIM containers to/from ICTT, inside the port at Q7 area, in the absence of facilities at ICTT, Vallarpadam. The COPT has proposed to recover charges for the pre-stage services, viz. (i) examination of import / export containers, (ii) lift on/lift off of containers (iii) electricity supply and reefer monitoring charges and (iv) ground rent. The existing Scale of Rates (SoR) of COPT does not prescribe tariff for these services except for levy of ground rent. Clause 2.17.1 of the tariff guidelines of 2005 provides that whenever a specific tariff for a service / cargo is not available in the notified SoR, the port operator can submit a suitable proposal.
- (ii). The COPT has proposed the charges on ad hoc basis stating that a cost based proposal would be submitted along with its proposal for general revision of SoR, which is due from 1 April 2012. It is relevant here to mention that the COPT has included the rates for these services in the proposed SoR furnished by it along with the proposal for general revision of its SoR. The proposal of COPT for general revision of its SoR is under the proceedings of this Authority. As it may take some more time for finalization of the general revision proposal and notification of the revised SoR, in view of the extension of time for submission of requisite details / clarifications sought by COPT, the proposal for approval of ad hoc rates is taken up for consideration.
- (iii). The rates proposed by the COPT for two tariff items, viz. lift on / lift off services and electricity supply & reefer monitoring services are at par with the tariff notified by this Authority for IGTPL for its operations at RGCT. The ground rent is proposed at the existing level of tariff prescribed in the SoR of COPT. The rate of ₹400/- per container proposed by COPT for examination of containers is reported to be an average of charges levied by IGTPL outside RGCT, prior to commencement of container handling operations at ICTT. Consequent to migration of IGTPL from RGCT to ICTT, the COPT has decided to continue the provision of pre-processing facility to ensure smooth movement of containers to and from ICTT.
- (iv).
  - (a). As stated earlier, the COPT has proposed to adopt the rates for lift on / lift off service and reefer monitoring service as prescribed in the Scale of Rates of IGTPL vide Order No.TAMP/34/2005-IGTPL dated 6 October 2005. Incidentally, the proposed rates are found to be in line with the rates approved in the Scale of Rates of IGTPL vide Sections 3.2.2 and 3.5 read with clause 2 (vii) prescribed in Order No.TAMP/34/2005-IGTPL dated 6 October 2005.
  - (b). As per clause 2.12 of the tariff guidelines of March 2005, when a new facility is commissioned, initial tariff to be allowed will not exceed the existing tariff level at the same port for comparable facilities. If such comparison is not available, prevailing tariff at comparable nearby port will be considered as the reference level. The initial tariff so adopted will be valid for the first year of operations where-after revised tariff will be fixed based on the admissible cost and investment of the operator. As stated earlier, the existing SoR of COPT approved by this Authority vide Order dated 23 February 2010 does not prescribe the charges for lift on / lift off and reefer monitoring services. It appears that in the absence of charges in its own Scale of Rates for such services, the COPT has adopted the charges prescribed in the Scale of Rates of IGTPL for similar services. Therefore, the adoption of the charges prescribed in the Scale of Rates of IGTPL by COPT follows the tariff guideline position.

- (c). As far as the levy of charges for the space occupied by the container at the pre-processing facility, the COPT has proposed to apply the ground rent prescribed in its own SoR without allowing free period. It appears that the COPT has proposed not to allow free period for the containers at the pre-processing facility since the containers are not meant for handling at its berths and it is not collecting wharfage and handling charges on such containers.
- (d). As brought out earlier, the COPT has proposed to levy charges for examination of containers @ ₹400/- per container irrespective of the size of the containers and timing of processing.

In the Order No.TAMP/48/2011-GTIPL dated 19 January 2012 passed by this Authority disposing off the proposal filed by the Gateway Terminals India Pvt. Ltd. (GTIPL) for general revision of its SoR, rates prescribed for stacking of containers for customs examination or for any other purpose ranges from ₹18.35 to ₹236.70 depending upon the size of the container. However, the proposal of the COPT is for prescription of a single rate irrespective of the size of the containers.

Though rates have been prescribed in the Scale of Rates of container terminals operated by CITPL, CCTPL and NSICT for examination of containers such rates relate to on-wheel inspection of the containers which may not be relevant for comparison with the rate proposed by the COPT. A rate of ₹170/- per container irrespective of the size of the container has been prescribed in the existing Scale of Rates of JNPT approved vide Order No.TAMP/53/2007-JNPT dated 18 February 2011 for stacking of the containers for customs examination or any other purpose. However, in the tariff Order recently passed by this Authority vide Order No.TAMP/10/2011-VCTPL dated 11 October 2011 and TAMP/40/2010-ABGKCTL dated 11 October 2011 disposing off the general revision proposals filed by VCTPL and ABGKCTL, a rate of ₹400/- and ₹356/- respectively has been prescribed irrespective of the size of the container for customs examination within the terminal. It is noteworthy that the rate proposed by the COPT is at par with the rate prescribed for VCTPL and closer to the rate prescribed for ABGKCTL.

- (e). Keeping in view the position that the rate for examination of containers proposed by the COPT is comparable with the rate prescribed in the SoR of VCTPL and ABGKCTL, the rates for lift on / lift off service and electricity supply & reefer monitoring service proposed by COPT follows the tariff guideline position and the ground rent proposed by COPT is drawn from rates already prescribed in the SoR of the port and recognizing the position that the users have endorsed the proposed rates, this Authority is inclined to approve the rates proposed by the COPT without any change for rendering the pre-processing services at the Q7 area of the port.
- (v). The Shipping Corporation of India (SCI) has made a request that the general conditionality laid down by TAMP to the effect that the ground rent will cease beyond 75 days in respect of abandoned FCL / shipper owned containers is inserted in the tariff clause itself to ensure that the port abides by the general rule. The existing approved Scale of Rates of COPT already contains the conditionalities governing the application of storage charges on abandoned FCL containers / shipper owned containers, which is binding on the COPT. Therefore, prescription of the said conditionalities in the SoR of COPT will be a mere repetition.

2465 62/12-4

- (vi). The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) has expressed concern about the charges levied by the Shipping companies. The charges levied by the shipping companies do not fall within the regulatory regime of this Authority.
- (vii). With reference to the request made by the Coffee Board that the cost incurred at Q7 area should be borne by the COPT till all facilities are made available at ICTT, it has to be recognized that the port is rendering additional services at Q7 area which involves additional cost to the port. Hence, it is not fair to expect the port to render such services free of cost.
- (viii). As per clauses 2.17.1 and 2.17.2 of the tariff guidelines of 2005, whenever a specific tariff for a service / cargo is not available in the notified SoR, the port can submit a suitable proposal. Simultaneously with the submission of proposal, the proposed rate can be levied on an ad hoc basis till the rate is finally notified. However, the ad hoc rate must be derived based on the existing notified tariffs for comparable services and it must be mutually agreed upon by the port and the concerned users. The port is already collecting the proposed charges on ad hoc basis from 21 February 2011 as seen from the Trade circular issued by the port with the consent of the users. The COPT has furnished documentary evidence for consent of users and the proposed charges have been derived based on the notified tariff for comparable services, except charges for examination of containers which is also comparable with the rates prescribed in the Scale of Rates of VCTPL and ABGKCTL, as stated earlier. Clause 2.17.4 of the tariff guidelines of 2005 enables this Authority to recognize the interim rate adopted in an ad-hoc manner retrospectively unless it is found to be excessive requiring some moderation retrospectively. Since no moderation is required in the rates proposed by the COPT, this Authority is inclined to recognize the rates levied by the port in an ad hoc manner from 21 February 2011, the date of implementation of the proposed rates till the effective date of implementation of the rates approved by this Authority.
- (ix). Since the port has already started collecting the proposed charges, the rates approved will come into force upon the notification of the Order passed in this case without any lead time.
- (x). The tariff guidelines stipulate a tariff validity cycle of 3 years. However, the rates proposed by the COPT in the subject proposal are on ad hoc basis. Further, the COPT has included the charges for these services in its proposal for general revision of its SoR which is under the proceedings of this Authority. That being so, it is appropriate to prescribe the validity of the rates approved in this case till the effective date of implementation of the SoR of the port to be approved by this Authority in the general revision proposal.
- (xi). The charges for pre-stage services is incorporated in the Scale of Rates of the COPT as a separate schedule under Chapter V – Container Related Charges.

8. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority approves the following charges which are incorporated as schedule 5.4 under Chapter V of existing Scale of Rates of the COPT:

**"5.4. Charges for pre-stage services to containers to/from ICTT**

**(a). Charges for examination of import & Export container for clearance:**

20'	40'	45'
₹ 400		

**(b). Lift on / Lift off charges for containers:**

Type	Foreign (in ₹)			Coastal (in ₹)		
	20'	40'	45'	20'	40'	45'
Laden	570.24	855.36	1140.48	342.14	513.22	684.29
Empty	178.20	267.30	356.40	106.92	160.38	213.84

- (c). Reefer charges for containers – Electricity supply and monitoring charges per 4 hours or part thereof.

Foreign (US \$)			Coastal (₹)		
20'	40'	45'	20'	40'	45'
3.18	4.76	6.35	138.40	207.58	276.80

- (d). Ground Rent on Containers:

Ground Rent will be levied for containers availing storage from the day following the date of grounding, at the rates prescribed at schedule 5.1.2 of the Scale of Rates of the port without allowing the free period prescribed therein."

RANI JADHAV, Chairperson  
[ADVT. III/4/143/12/Exty.]